“आत्मनिर्भर भारत
130 करोड़ भारतवासियों के लिए
आज एक मंत्र बन गया है”

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण

दिसंबर 2020

रेल मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की उपलब्धियां

रेल मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान :
14 लाख से अधिक मानव दिवस के रोजगार का सृजन

राष्ट्र की जीवन रेखा- कोविड-19 के दौरान

श्रमिक दिवस (1 मई 2020) से
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन आरम्भ

4,621	श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं
63.1 लाख	प्रवासी श्रमिक ले जाये गए
1.85 करोड़	खाने के पैकेट का वितरण
2.21 करोड़	पानी के बोतल की निशुल्क आपूर्ति

5,601 ट्रेन कोच, कोविड केयर केन्द्र में परिवर्तित

17 समर्पित चिकित्सालयों में **5,000** बेड आरक्षित

33 पृथक चिकित्सालय ब्लाक भी कोविड केयर हेतु आरक्षित

कोविड के उपरांत यात्रा के लिए महत्वपूर्ण डिजाईन सुधार के साथ दुनिया के पहले **कोविड-सुरक्षित** कोच का अनावरण किया

आपदा को अवसर में बदलती रेलवे

कोविड-19 के दौरान सद्भावना बढ़ाती रेलवे

आवश्यक सामग्रियों जैसे कि खाद्यान्न, कोयला, पेट्रोलियम, खाद, लौह अयस्क एवं अन्य की आपूर्ति

टाइम टेबल्ड पार्सल ट्रेनें आरम्भ - 1 अप्रैल से 30 सितम्बर 2020 तक **8.3 लाख** टन सामग्री की ढुलाई

खाद्यान्नो की रिकॉर्ड लोडिंग

(1 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2020)

3.9 करोड़ टन
2020

2.1 करोड़ टन
2019

कनेक्टिविटी का इंजन

694 विशेष ट्रेनें, **436** पूजा विशेष ट्रेनें, **1,410** मुंबई उपनगरीय सेवा, **200** कोलकाता मेट्रो एवं **28** सवारी ट्रेनें शुरू की गयीं

मेक इन इंडिया के क्षेत्र में उपलब्धियां

5.5 लाख पीपीई किट (कवर ऑल)

1.4 लाख लीटर सैनिटाइजर

20 लाख पुन: उपयोगी फेस कवर

इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

350 बड़ी परियोजनाओं को पूरा कर सुरक्षा एवं गति में सुधार

रेल सुरक्षा

सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन :

अप्रैल 2019 से अभी तक किसी भी यात्री की मृत्यु नहीं

भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार

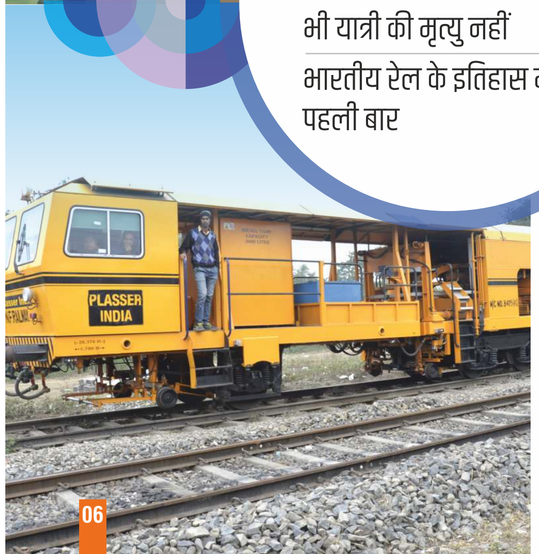

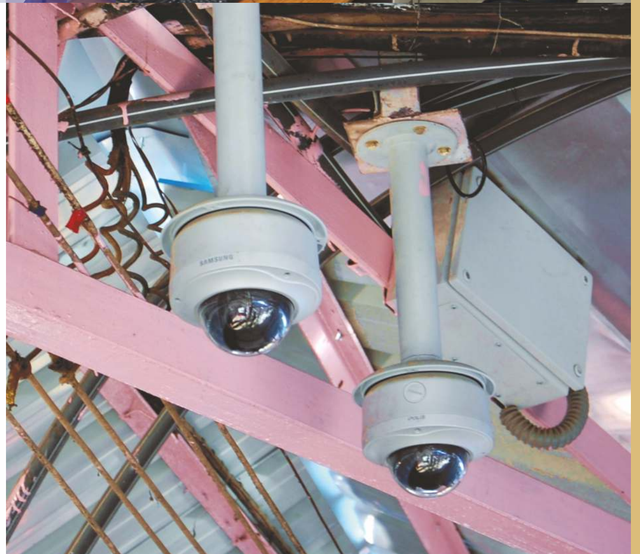

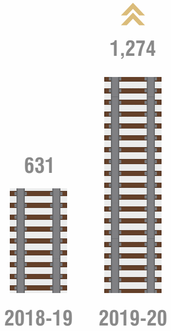

मानव युक्त क्रासिंग को समाप्त करने की दर में **102% की बढ़ोत्तरी**

पुलों के सुदृढ़ीकरण में **35% की बढ़ोत्तरी**

ट्रैक नवीनीकरण के एरियर्स में तेजी से कमी

रेल सुरक्षा के लिए कमांडो '**कोरस**' की शुरुआत

2019-20 में **132 स्टेशन** पर सीसीटीवी आधारित सर्विलांस प्रणाली का प्रावधान

अब तक कुल **627** स्टेशन पर सीसीटीवी प्रणाली लगायी जा चुकी है

इंफ्रास्ट्रक्चर- एक बेहतर कल के लिए

2014-20 में पूंजीगत व्यय ₹6,45,600 करोड़, 60 वर्षों 1951 से 2014 में हुए संचयी निवेश (₹4,95,958 करोड़) को पार कर गया

1,353 किमी लम्बी, 32 परियोजनाएं पूर्ण

गोल्डन क्वाड्रीलेटरल / गोल्डन डायगनल के मार्गों पर पारंपरिक 1x25 kV से 2x25 kV कर्षण की ओर अग्रसर

बीना-कटनी-विश्रामपुर खंड और डीएफसी में पहले से ही कार्यशील

नई दिल्ली – मुंबई और **नई दिल्ली – हावड़ा** को 2024 तक पूरा कर लिया जायेगा

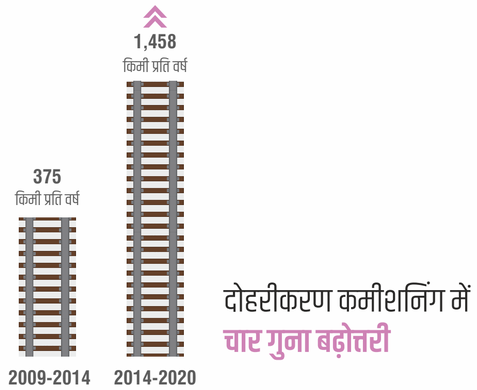

दोहरीकरण कमीशनिंग में
चार गुना बढ़ोत्तरी

पूर्वोत्तर : सातो राज्यों से कनेक्टिविटी

त्रिपुरा में 112 किमी लंबी
अगरतला – सबरुम रेल लाइन पूर्ण

लामडिंग से होजाई 45 किमी लंबी दोहरीकरण परियोजना पूर्ण

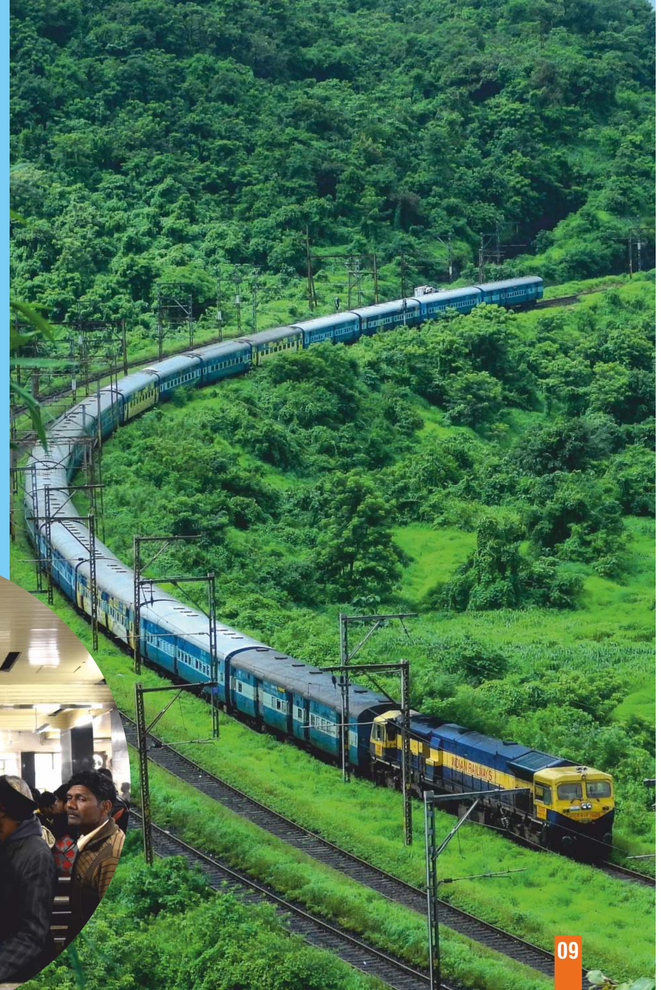

आत्मनिर्भर भारत

नये भारत की ताकत,
आत्मनिर्भर भारत

प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में बदलाव : इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के **95% से ज्यादा कलपुर्जे** स्वदेशी स्रोत से लिए जायेंगे

रेल व्हील फैक्ट्री (आरडब्ल्यूएफ) में **ऐक्सल क्षमता** में बढ़ोत्तरी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी

वन्दे भारत ट्रेन के **44 रेकों** के प्रोक्योरमेंट की शुरुआत

मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स को बढ़ाया गया

निर्यात में तेजी
बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी ने **श्रीलंका रेलवे को 7 डीजल रेल इंजन** निर्यात किए

रोलिंग स्टॉक के उत्पादन में बढ़ोत्तरी

605
2018-2019

784
2019-2020

इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उत्पादन में **30% की बढ़ोत्तरी**

4,429
2018-2019

6,277
2019-2020

एलएचबी कोचों के उत्पादन में **42% की बढोत्तरी**

स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत

100%
कोच बायो-टॉयलेट युक्त

953 स्टेशनों पर इंटीग्रेटेड मेकेनाइज्ड क्लीनिंग की सुविधा उपलब्ध

ग्रीन रेलवे

इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य में **4.5 गुना की बढ़ोत्तरी**

12,000 हॉर्सपावर के 43 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक लोको का विनिर्माण

960 बड़े रेल भवनों के छतों पर लगाये गए **103 मेगावाट** के सोलर पॉवर प्लांट प्रारम्भ

103.4 मेगावाट विंड पॉवर प्लांट प्रारम्भ

स्किलिंग भारत

राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान-
डीम्ड यूनिवर्सिटी एवं
राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

2018 से क्लासेस प्रारम्भ

20 राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों
से **200** विद्यार्थी

2 प्रोग्राम
(3 वर्षीय - बी.एससी. एवं बी.बी.ए.)

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के कार्य में तेजी

पश्चिमी डीएफसी में **306 किमी लम्बी रेवाड़ी – मदार खंड** का कार्य पूर्ण

पूर्वी डीएफसी में **194 किमी लम्बी खुर्जा – भदान खंड** का कार्य पूर्ण

डीएफसी के लाभ :

माल का आसान, तीव्रगामी एवं निर्बाध आवागमन

कारखानों एवं कृषि क्षेत्रों से बंदरगाहों की कनेक्टिविटी से आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन

माल-परिवहन में तेजी

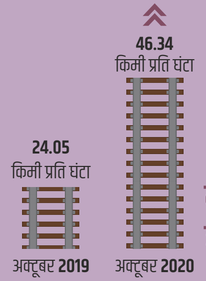

मालगाड़ियों की रफ़्तार लगभग दोगुनी

टाइम टेबल में उच्च गति मानक अंकित

टाइम टेबल में मालगाड़ियों के संचालन एवं रखरखाव कार्य के लिए अलग – अलग कॉरिडोर सम्मिलित

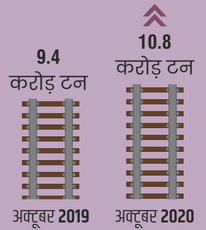

माल ढुलाई में 15.4% की वृद्धि

नए वैगनों के इंडक्शन में **22% की वृद्धि**

सभी निजी साइडिंग को निजी फ्रेट टर्मिनल बनाने की अनुमति

बांग्लादेश को निर्यात के लिए नई संशोधित माल (एनएमजी) रेक के माध्यम से ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट आरम्भ

गुड्स शेड्स को निजी निवेश के माध्यम से विकसित करने हेतु पॉलिसी जारी

यूट्यूब वीडियो

माल ढुलाई में अग्रसर

मालभाड़ा दरों का उपयुक्तिकरण

15% बिजी सीजन सरचार्ज समाप्त

टू पॉइंट कॉम्बिनेशन एवं मिनी रेक पर लगने वाला 5% सप्लीमेंट्री चार्ज समाप्त

इंडस्ट्रियल सॉल्ट के रेट क्लास को घटाया

ई – पेमेंट सुविधा आरम्भ

माल लदान से जुड़े 1,268 ग्राहक ई-पेमेंट सुविधा का लाभ ले रहे हैं

अनुमोदित रियायतें

लम्बी दूरी: कोयला, लौह अयस्क एवं फिनिश्ड स्टील पर 15 से 20%

छोटी दूरी: सभी कार्गो (कोयला एवं लौह अयस्क छोड़कर) पर 10 से 50%

कन्टेनर यातायात: भरे हुए पर 5% तथा खाली पर 25%

फ्लाई ऐश : 40%

किसान रेल से कृषि क्षेत्र में खुशहाली

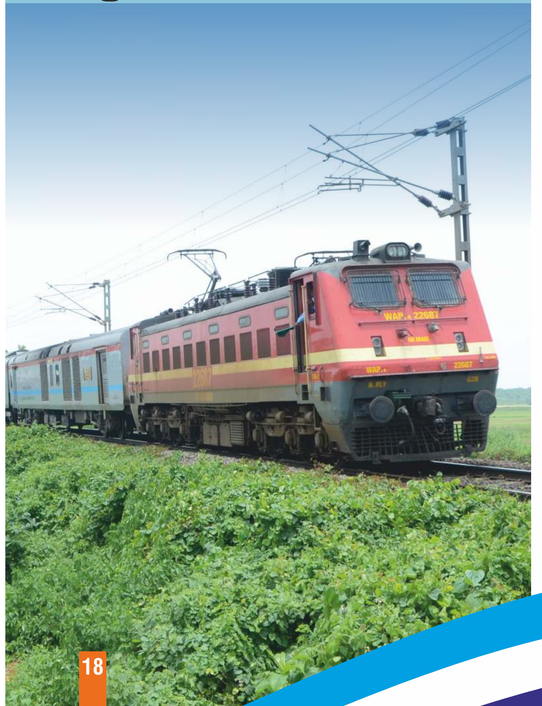

बजट 2020 – पीपीपी के माध्यम से दूध, मांस एवं मछली सहित पेरिशेबल आइटम्स की राष्ट्रीय स्तर पर निर्बाध रूप से तापमान नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला हेतु **'किसान रेल'** का आरम्भ

अगस्त 2020 में प्रथम सेवा - पायलट प्रोजेक्ट के रूप में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार को जोड़ते हुए - **देवलाली से दानापुर** - के मध्य चलायी गयी

अब मांग पर मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया गया

दो **किसान रेल** और शुरू की गयीं

किसान रेल में अधिसूचित सब्जियों एवं फलों के परिवहन पर **50%** की छूट

प्रोटीन कन्टेनर विशेष ट्रेन (दादरी से जेएनपीटी/मुन्द्रा/पिपवाव) प्रारम्भ – 144 फेरे (अप्रैल - जुलाई 2020)

यात्रियों की मुस्कान के लिए निरन्तर प्रयास

विस्टाडोम कोच : पर्वतीय पर्यटन स्थलों के यात्रा अनुभवों को यादगार बनाने हेतु पारदर्शी एवं आकर्षक चित्रों से युक्त 30 विस्टाडोम कोच उपयोग में लाये जा रहे हैं

दिल्ली - लखनऊ एवं मुंबई - अहमदाबाद रेल मार्गों पर आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त **दो तेजस ट्रेनें** चलायी गयी

नई दिल्ली से कटड़ा के मध्य आधुनिक यात्री सुविधाओं से परिपूर्ण दूसरी **वन्दे भारत एक्सप्रेस** को नियमित सेवा में शामिल किया गया

134 नई ट्रेनों की शुरुआत की, **118** ट्रेनों की सेवाओं को बढ़ाया गया और **22** ट्रेन सेवाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई

अगस्त और सितंबर में गणपति उत्सव, **जेईई / एनईईटी परीक्षा** और **एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा** के लिए मांगों के अनुसार, राज्य सरकारों के समन्वय से विशेष ट्रेनें संचालित

कुछ खास क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए रणनीति के तहत क्लोन ट्रेनों का संचालन आरम्भ

अधिक वेटलिस्ट वाले अत्यधिक संरक्षित ट्रेनों के क्लोन के रूप **20** जोड़ी विशेष ट्रेनों का आरम्भ

प्रगति का प्लेटफॉर्म

5,814 स्टेशनो पर तेज वाई-फाई की निशुल्क सुविधा (वर्ष 2019-20 में 4,411 स्टेशनों पर)

वर्ष 2019-20 में **835 रेलवे स्टेशनों** पर एयरपोर्ट मानक के स्तर की उन्नत प्रकाश व्यवस्था

सुगम्य टिकटिंग व्यवस्था

आई.आर.सी.टी.सी. – एस.बी.आई. रुपे कार्ड 28 जुलाई 2020 को जारी किया जिससे बारम्बार यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को बचत होगी, ट्रान्जेक्शन फीस पर छूट एवं आनन्दमय शॉपिंग का अनुभव मिलेगा

अयोध्या रेलवे स्टेशन का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण

नया स्टेशन भवन, दो आधुनिक फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफार्म सुधार एवं सरकुलेटिंग एरिया का विकास कार्य ₹105 करोड़ की लागत से किया जाना है, यह परियोजना 2020-21 में पूर्ण होगी

परिचालन में पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप

पीपीपी प्रणाली के अनुरूप 109 रेल मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनें (रेक)

उन्नत तकनीक

यात्रा समय में कमी; यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव

रेल क्षेत्र में निजी निवेश
~ ₹30,000 करोड़ अनुमानित

विकास की रेल

बिहार में रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए **कोसी रेल मेगा ब्रिज** का उद्घाटन

बिहार में ₹2,720 करोड़ की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमे नई रेल लाइन, इलेक्ट्रिक लोको शेड, गेज परिवर्तन एवं विद्युतीकरण शामिल हैं

पटना – नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने रेलवे के **"मिशन रफ़्तार"** के तहत पहली बार पटना से नई दिल्ली के बीच **130 किलोमीटर प्रति घंटे** की रफ़्तार से चल कर एक रिकॉर्ड बनाया

तीव्र रेल गतिमान रेल

कार्यशीलता के आधार पर रेलवे बोर्ड का **पुनर्गठन**

रेलवे बोर्ड में अब **मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह अध्यक्ष रेलवे बोर्ड**

विभागीय आधार पर 8 सदस्यों के स्थान पर कार्यशीलता के आधार पर **4 सदस्य**

एकल सेवा का अनुमोदन
वर्तमान में 8 सेवा के स्थान पर भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (भा.रे.प्र.से.)

1.4 लाख रिक्त पदों की ओपन मार्केट से भर्ती के लिए **2.56 करोड़** अभ्यर्थियों का कंप्यूटर आधारित टेस्ट कराया गया

12 लाख रेल कर्मचारियों के लाभ हेतु ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेवाओं का शुभारम्भ किया गया

पारदर्शिता एवं जवाबदेही

रेल दृष्टि:
पोर्टल के माध्यम से आमजन को रेलवे के प्रमुख कार्यों की जानकारी

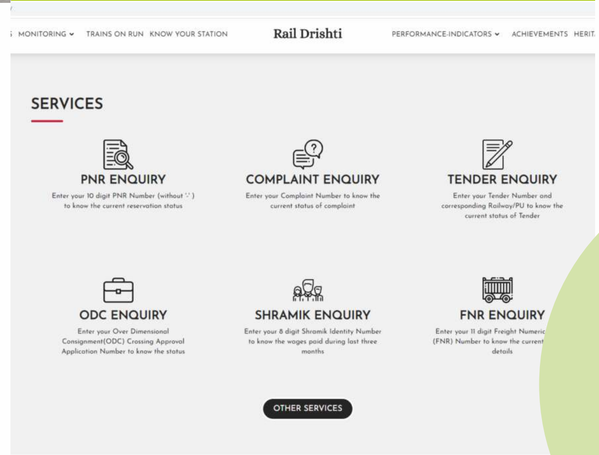

आईआरईपीएस एवं जीईएम का एकीकरण

इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम (आईआरईपीएस) का गवर्नमेंट ई – मार्केट प्लेस (जीईएम) के साथ एकीकरण शीघ्र पूरा होगा

दोनों की प्रमुख विशेषताएं यथावत रहेंगी

प्रोक्योरमेंट में पारदर्शिता एवं डिजिटलीकरण के नए युग का उदय

वृहद् वेंडर आधार एवं आपूर्ति इकोसिस्टम का विकास

इंडियन रेलवे प्रोक्योरमेंट **(₹70,000 करोड़)** का जीईएम में ट्रांजिशन

ई – रिवर्स नीलामी ₹5 करोड़ से अधिक मूल्य के सामान के क्रय हेतु टेंडरिंग प्रक्रिया में अब डिफ़ॉल्ट मोड

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की उपलब्धियां

दिसंबर 2020

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कोविड-19 के दौरान निर्यातकों एवं एमएसएमई को राहत

विदेश व्यापार नीति को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया

एडवांस ऑथोराइज़ेशन देने की वैधता को 6 माह के लिए बढ़ाया गया

एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड को 6 माह के लिए बढ़ाया गया

3 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान वाली आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (इसीएलजीएस) एमएसएमई के लिये 100% क्रेडिट गारंटी और कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक ऋण है

निर्यात लाइसेंस संबंधी आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को संशोधित किया गया

प्याज, काजू और पाम ऑयल जैसी मूल्य संवेदनशील सामग्रियों के **आयात और निर्यात को विनियमित** करने के लिए समय पर उपाय

कोविड-19 हेल्पडेस्क

एमएसएमई में इक्विटी इन्फ्यूज़न के लिए फंड ऑफ फंड्स और रियायती ऋण के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त सहायता

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए क्रेडिट सुविधा (पीएम स्वनिधि योजना)

आत्मनिर्भर भारत : आपदा को अवसर में बदलना

57,600 वेंटीलेटर का निर्माण केवल तीन महीनो में किया, जबकि कोविड से पहले घरेलु स्तर पर लगभग कोई वेंटीलेटर नहीं बनता था

4 गुना बढ़ोत्तरी हुई सैनिटाइज़र उत्पादन में, 200 डिस्टिलरी और 1,000 निर्माताओं द्वारा

5 लाख पीपीई प्रतिदिन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता

नये भारत की ताकत,
आत्मनिर्भर भारत

वसुधैव कुटुम्बकम : मानवता की सेवा

मानवीय आधार पर **120 देशों** को दवाइयों पर छूट दी गई

'मेक-इन-इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए पीपीई मेडिकल कवर ऑल, सर्जिकल मास्क, मेडिकल चश्मे और सैनिटाइज़र के निर्यात की अनुमति दी

MAKE IN INDIA

लोकल से ग्लोबल की ओर

भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए 24 प्राथमिकता वाले क्षेत्र

विशेषज्ञों और उद्योग हितधारकों के परामर्श से चिन्हित किए गए

घरेलू क्षमताओं पर निर्माण करना

सुगमता और नीतिगत समाधानों के माध्यम से वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने एवं रोजगार सृजन करने के लिए

$526 बिलियन 2019-20 में कुल निर्यात (सेवा और वस्तुएं), आधा ट्रिलियन से अधिक

$3.6 बिलियन बिलियन मूल्य के मसालों का निर्यात 2019-20 में अब तक के उच्चतम स्तर पर

100 आदिवासी उत्पादों की प्रोत्साहन के लिए पहचान की गई

500 जिलों के लिए निर्यात क्षमता वाले विशिष्ट उत्पादों की पहचान की गई

घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर क्षेत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम और नियमों में संशोधन किए गए

लगभग **$47 बिलियन** के फोकस प्रोडक्ट्स के आयात के लिए **टेक्निकल रेगुलेशंस (टीआर)** - यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम गुणवत्ता वाले और हानिकारक उत्पाद बाजार में प्रवेश न करें

173 वस्तुओं पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गई और **44 वस्तुएं** निषेध/प्रतिबंधित की गई

शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार : एंटी डंपिंग जांच आरंभ करने के लिए औसत समय को कम करके 33 दिन किया गया

आवेदन करने हेतु घरेलू उद्योग, विशेषकर **एमएसएमई**, की सहायता के लिए हेल्पडेस्क

पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा

बजटीय सहायता योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित **औद्योगिक इकाइयों को 2,130 करोड़ रुपये वितरित किए गए**

हिमालयी राज्यों के लिए **विशेष पैकेज योजना के तहत ₹578** करोड़ रुपये का वितरण किया गया

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए **नई औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस)** को दिनांक 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया

भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग नक़्शे पर

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य 4 औद्योगिक क्षेत्रों में पूरा होने वाला है, धोलेरा औद्योगिक सिटी, गुजरात; शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र; एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश; आईआईटी विक्रम उद्योगपुरी, मध्य प्रदेश

सभी प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट पर **लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक परियोजना** को सफलतापूर्वक लागू किया गया

मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्य उद्योगों को लगाने हेतु निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जीआईएस युक्त **लैंड बैंक** पोर्टल का शुभारम्भ

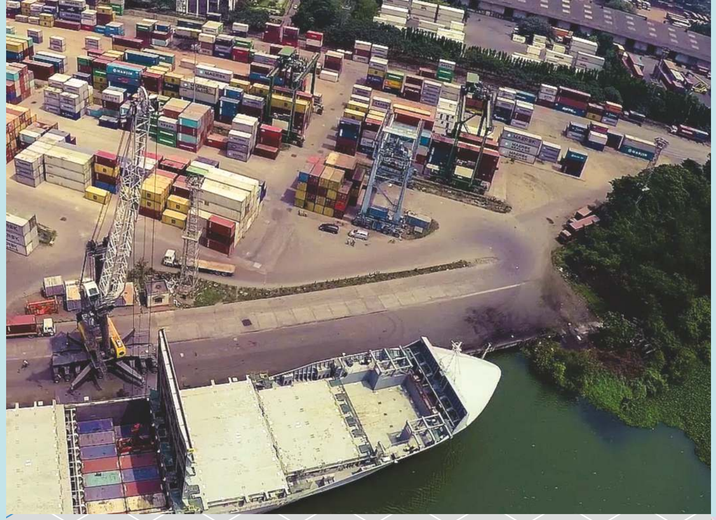

व्यापारिक वार्ता क्षेत्र में भारत अग्रणी

भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में सफलतापूर्वक अपना पक्ष रखा

भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा में अच्छी प्रगति

निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय निर्यात पर लगाई गई विभिन्न **नॉन टैरिफ अवरोध** से संबंधित नियमित हस्तक्षेप

भारत ने एफटीए की समीक्षा के लिए आसियान में पहले ही अनुबंध कर लिया है – यह भारतीय निर्यात और मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा देने में सहायता करेगा

एफडीआई इनफ्लो में वृद्धि

एफडीआई में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि

कोयला खनन गतिविधियों और अनुबंध विनिर्माण में **100 प्रतिशत** एफडीआई की अनुमति

स्थानीय सोर्सिंग द्वारा **सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग (एसबीआरटी)** में सुलभ और लचीला संचालन

अवसरवादी नियंत्रण/अधिग्रहण से भारतीय कंपनियों की सुरक्षा के लिए **एफडीआई नीति में संशोधन** किया गया

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में शीर्ष 10 सुधारकर्ताओं में

भारत ने 10 में से **7 संकेतकों में अपनी रैंक में सुधार** किया है

भारत लगातार तीसरी बार शीर्ष 10 सुधारकर्ताओं में से एक है और 3 वर्षों में **67 स्थान** का सुधार किया

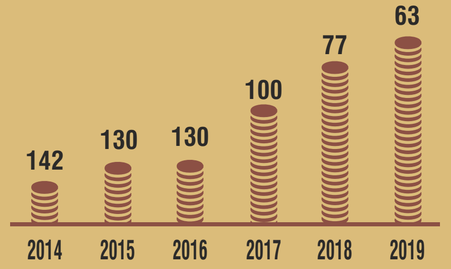

वर्ष 2019 के लिए बिजिनेस रिफार्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की घोषणा की गई

यह प्रत्येक राज्य में निवेश आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में सहायक होगा

पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) के माध्यम से पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रक्रिया

तीसरे पक्ष का निरीक्षण सरकारी निरीक्षणों के अनुरूप

इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल की स्थापना की दिशा में कार्यरत

व्यवसाय संचालन आरंभ करने के लिए आवश्यक सभी केंद्रीय और राज्य मंजूरी प्राप्त करने हेतु वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म

~ 930 फार्म और मंजूरी की पहचान की गई

सरकारी खरीद में मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा

₹200 करोड़ से कम की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडरिंग की आवश्यकता नहीं

50 प्रतिशत से अधिक की स्थानीय सामग्री के साथ स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता

भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधात्मक स्थितियों के कारण **37,000 करोड़** रुपये से अधिक की निविदाएं रद्द/संशोधित की गई

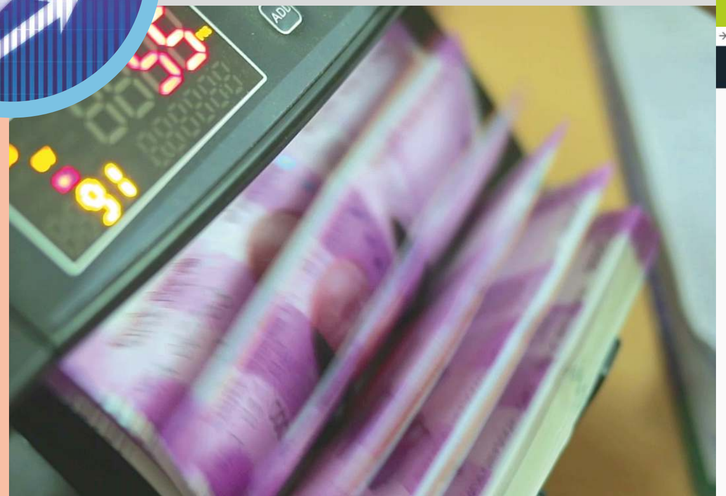

जीईएम के साथ प्रोक्योरमेंट को नया रूप

जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस)
- छोटे व्यवसाय और एमएसएमई के लिए वरदान

एक पारदर्शी, कुशल और तेज पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रणाली

ई-कॉमर्स में समान अवसर

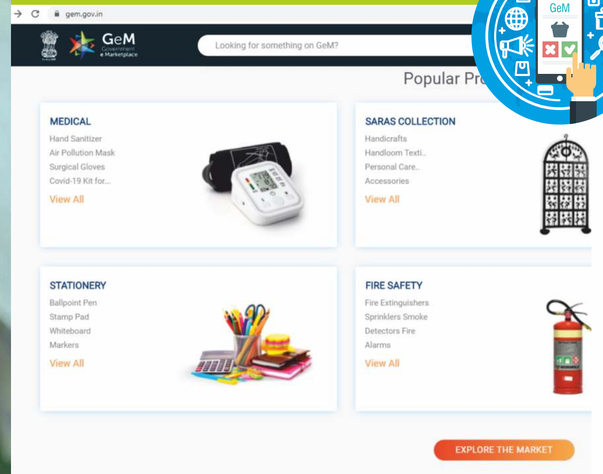

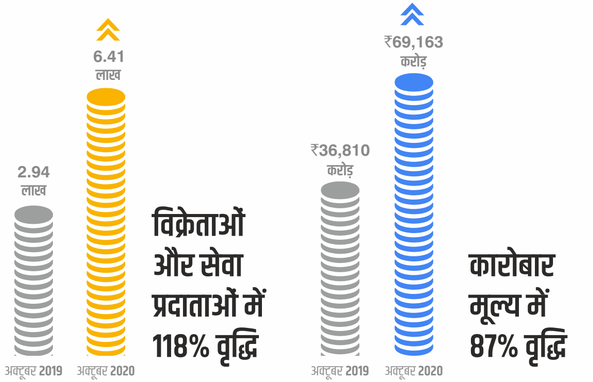

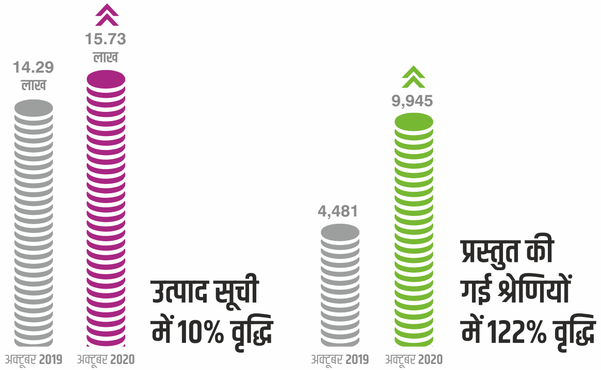

इनोवेट इन इंडिया

2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान पेटेंट देने में **63 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है

छोटे व्यवसाय/एमएसएमई के लिए **पेटेंट आवेदन प्रोसेसिंग** शुल्क को कम किया

पेटेंट आवेदन की जांच की समय-सीमा को मई 2019 में **36-52 माह** से कम करके मई 2020 में 12-30 माह किया गया

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में 81 वें स्थान से छलांग लगा कर 2019 में **48 वें स्थान** पर पहुंच गया

21 नए भारतीय भौगोलिक संकेत (जीआई) जीआई रजिस्ट्री में पंजीकृत किए गए (मई 2019 से मई 2020 तक)

स्टार्टअप इंडिया को दिए नए पंख

37,000 से अधिक स्टार्ट-अप्स को मान्यता दी गई। 50 प्रतिशत से अधिक को मई 2019 से मान्यता दी गई

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए

पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार - 35 श्रेणियों में 1,641 स्टार्टअप्स ने भाग लिया

2,785 पेटेंट आवेदनों को फाइलिंग शुल्क में 80 प्रतिशत और 5,494 ट्रेडमार्क आवेदनों पर 50 प्रतिशत की छूट

देश भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुधारने हेतु स्टार्टअप इकोसिस्टम को दिए गए प्रोत्साहन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया

स्टार्टअप को विकसित करने की सुविधा के लिए 39 विनियामक सुधार किए गए

आयकर अधिनियम की धारा 54 जीबी में संशोधन के तहत पूंजीगत लाभ पर कर में छूट का प्रावधान

धारा 80 आईएसी के तहत 3 वर्ष की आयकर अवकाश अवधि और आयकर अधिनियम की धारा 79 के तहत योग्य हानियां कैरी फारवर्ड करने की सुविधा

योग्य स्टार्टअप के लिए टर्नओवर मानदंड का विस्तार ₹100 करोड़ रुपये

अगस्त 2020 तक, 296 स्टार्टअप्स को आयकर अधिनियम के तहत छूट दी गई थी

ई-गवर्नेंस के साथ सुगम व्यापार

सभी **निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं** अर्थात् अग्रिम, ईपीसीजी, एमईआईएस ऑनलाइन संचालित

इस्पात आयात मॉनीटरिंग प्रणाली (एसआईएमएस) के लिए **ऑनलाइन अंतर-मंत्रालयी परामर्श** मॉड्यूल लागू

डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन (सीओओ) जारी करने के लिए **इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (ईसीओओ)** आरंभ किया गया। **20,000 से अधिक सीओओ जारी**

एल्युमीनियम, कॉपर, फुटवेयर, फर्नीचर, पेपर, खेल-कूद के सामान, जिम के उपकरण आदि के लिए आयात निगरानी प्रणाली (आईएमएस) विकसित की जा रही है

डिज़ाइन इन इंडिया के लिए अप-स्किलिंग

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019, संसद द्वारा पारित किया गया

आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा में **4 नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी)** को 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' का रूप प्रदत्त किया गया

डिजाइन संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण में **उत्कृष्टता को बढ़ावा**